RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 14 से 20 मार्च 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-83 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

रिलायंस अमेरिका में 50 साल बाद पहला नया तेल रिफाइनरी लगाएगी: ट्रंप ने टेक्सास के 300 अरब डॉलर प्रोजेक्ट को 'ऐतिहासिक सौदा' बताया

टेक्सास में 300 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट, 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता; भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत, अमेरिका में रोजगार और निवेश को बढ़ावा

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में 50 साल बाद पहला नया तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। टेक्सास में प्रस्तावित यह 300 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'ऐतिहासिक सौदा' बताते हुए कहा कि यह अमेरिका-भारत संबंधों का नया अध्याय है और लाखों रोजगार पैदा करेगा।

प्रोजेक्ट टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी क्षेत्र में विकसित होगा, जहां पहले से रिलायंस की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हैं। यह रिफाइनरी हाई-ग्रेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स और विशेष ईंधन का उत्पादन करेगी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, यह निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और अमेरिका में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। प्रोजेक्ट से 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

ट्रंप ने कहा, यह सौदा अमेरिका को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगा और भारत के साथ हमारा सबसे मजबूत आर्थिक रिश्ता बनेगा। यह प्रोजेक्ट भारत के बढ़ते तेल आयात को संतुलित करने और अमेरिकी शेल ऑयल का उपयोग करने की रणनीति का हिस्सा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में मजबूत स्थिति देगा। हालांकि, पर्यावरणविदों ने प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है। रिलायंस ने कहा कि यह प्लांट पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से बनेगा। यह सौदा भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय है।

ईरान-इज़राइल युद्ध: हर 10% तेल मूल्य वृद्धि से भारत की GDP ग्रोथ में 20-25 bps की कटौती हो सकती है: HDFC बैंक

तेल आयात पर निर्भरता से महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ने का खतरा; RBI की मौद्रिक नीति पर भी असर, ऊर्जा सुरक्षा के लिए तत्काल कदम जरूरी

नई दिल्ली: ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। HDFC बैंक की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि तेल की कीमतों में हर 10% की वृद्धि भारत की GDP ग्रोथ को 20-25 आधार अंक (bps) तक कम कर सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी कुल जरूरत का 85% से अधिक तेल आयात करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल हो जाती है, तो भारत का आयात बिल 30-35 अरब डॉलर बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ेगी, चालू खाता घाटा गहराएगा और रुपये पर दबाव बढ़ेगा। HDFC बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, तेल की कीमतों में उछाल से परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर उपभोग और निवेश पर पड़ेगा।

वर्तमान में ईरान-इज़राइल संघर्ष से होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से वैश्विक तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। यदि स्थिति बिगड़ती है तो तेल की कीमतें 120-150 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। इससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 15-20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को रूस, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ाना चाहिए। साथ ही, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना होगा। RBI को भी ब्याज दरों में कटौती पर विचार करना पड़ सकता है। यह युद्ध भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है।

चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश अब आसान: 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी

प्रेस नोट 3 में संशोधन से FDI नियम सरल, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी सेक्टर में निवेश तेज होगा; विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों (चीन सहित) से भारत में निवेश को और आसान बनाने के लिए FDI नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब इन देशों की कंपनियां किसी भी सेक्टर में 10% तक की हिस्सेदारी बिना सरकारी मंजूरी के खरीद सकती हैं। पहले प्रेस नोट 3 के तहत पड़ोसी देशों से सभी निवेश के लिए अनिवार्य मंजूरी की जरूरत होती थी, जिससे कई प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नया प्रेस नोट जारी कर कहा है कि रक्षा, रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर में 10% से कम हिस्सेदारी के लिए ऑटोमैटिक रूट लागू होगा। इससे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियां अब तेजी से निवेश कर सकेंगी। हालांकि, 10% से अधिक हिस्सेदारी या नियंत्रण वाली निवेश के लिए अभी भी सरकारी मंजूरी जरूरी रहेगी।

यह बदलाव ऐसे समय आया है जब भारत में FDI प्रवाह को बढ़ावा देने की जरूरत है। FY25 में FDI में 10% से अधिक की गिरावट आई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार सृजन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाएगा। चीन से आने वाले निवेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के साथ संतुलित तरीके से विदेशी पूंजी आकर्षित करने की कोशिश है। निवेशक और उद्योग जगत ने इस बदलाव का स्वागत किया है।

Cheques & Balances: IDFC First Brings in Extra Layer of Security

New Multi-Factor Cheque Verification System Reduces Fraud Risk; Bank Aims to Make Paper-Based Payments Safer in Digital Era

Mumbai: IDFC First Bank has introduced an innovative multi-factor security layer for cheque transactions, marking a significant upgrade to traditional paper-based payments. The new system, rolled out across all branches and digital channels, combines biometric authentication, dynamic QR codes, and real-time OTP validation to verify high-value cheque issuances and deposits.

Under the updated process, customers issuing cheques above ₹50,000 must authenticate the transaction via their registered mobile number through an OTP and Aadhaar-linked biometric scan (fingerprint or iris) at the time of cheque issuance or through the bank's mobile app. For cheque deposits, the presenting bank generates a dynamic QR code on the payee's passbook or app, which the payer must scan and confirm using their registered device. This creates a verifiable digital trail, making it extremely difficult for fraudsters to forge or misuse cheques.

Cheque fraud remains one of the few persistent vulnerabilities in our payment ecosystem, said V. Vaidyanathan, MD & CEO, IDFC First Bank. By adding multiple real-time layers of authentication, we are bringing cheques closer to the security standards of digital payments while preserving their utility for millions of customers.

The bank reported a sharp decline in cheque-related fraud cases in pilot branches where the system was tested. The initiative is particularly relevant in semi-urban and rural areas, where cheques are still widely used for business payments, property transactions, and government disbursements.

Industry observers welcomed the move, noting that while UPI and digital payments dominate, cheques still account for nearly 20% of high-value transactions in India. The enhanced security could help retain trust in paper instruments and reduce disputes. IDFC First Bank shares rose on BSE following the announcement. As cyber frauds continue to rise, the bank's proactive step may prompt other lenders to follow suit, strengthening overall payment system resilience in the country.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Food, Fertilizer and Fuel: Beyond Oil Prices: Deeper Economic Risks from the Iran–Israel War

When news of the Iran–Israel conflict appears in headlines, most people immediately think about rising crude oil prices. While oil is indeed the first and most visible impact, the real economic risks go much deeper. The conflict in West Asia is also affecting food supply, fertilizer availability, and fuel costs, which can influence everyday life for millions of people in countries like India.

The Middle East is one of the most important regions for global energy and trade. A key shipping route called the Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the rest of the world. This narrow sea passage handles a large share of global oil, gas, and fertilizer shipments. When tensions rise or shipping becomes risky, the entire global supply chain gets disturbed.

Most discussions focus on fuel prices because oil is the lifeline of modern economies. If oil prices rise, transportation becomes expensive, electricity costs increase, and the prices of many products go up. For India, the impact is even stronger because the country imports about 85% of its crude oil requirements. Higher oil prices increase the import bill, weaken the rupee, and push inflation higher.

However, the hidden risk lies in fertilizers, which are essential for agriculture. India imports a large quantity of fertilizers and fertilizer raw materials from countries in the Middle East. In fact, India imported about $3.7 billion worth of fertilizers from West Asia in 2025, including nitrogen and mixed fertilizers used for crops. If the conflict disrupts shipping routes or production in the region, fertilizer supply could tighten.

This has serious consequences for farmers. Fertilizers such as urea, DAP, and potash are necessary to maintain crop productivity. If fertilizer prices rise or supplies become limited, farmers may reduce usage, which can affect agricultural output. Lower crop yields eventually lead to higher food prices for consumers.

The problem does not stop there. Fertilizer production itself depends heavily on natural gas; another resource widely produced in the Gulf region. If gas supplies become uncertain due to conflict or shipping disruptions, fertilizer factories may cut production. In fact, some fertilizer companies in India have already warned of potential supply challenges if the conflict continues.

Rising diesel prices add another layer of pressure. Diesel is widely used in agriculture for tractors, irrigation pumps, and transportation of food grains. A rise in diesel prices increases the cost of farming as well as food distribution. According to analysts, global diesel markets are already facing supply disruptions due to tensions in the Middle East.

For common people, this chain reaction eventually appears in everyday expenses. Higher fuel prices increase transportation costs. Expensive fertilizers raise farming costs. Together, they push up the prices of vegetables, grains, and other food items.

The broader economic impact can also affect India's growth. Experts warn that if oil prices remain very high for a long time, inflation could increase and economic growth could slow down. The government may also have to increase subsidies for fertilizers and fuel to protect farmers and consumers.

In simple terms, the Iran–Israel conflict is not only about geopolitics or oil markets. It affects fuel, farming, food prices, and overall economic stability. Even though the conflict is happening thousands of kilometres away, its economic ripple effects can reach households across India.

The situation remains uncertain, but it clearly shows how deeply connected the global economy has become. A disruption in one region can influence energy prices, agriculture, and inflation across the world. For India, careful management of energy imports, fertilizer supplies, and food security will be crucial in navigating this challenging period.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

केदारा कैपिटल 3,000 करोड़ में यूनिवर्सल न्यूट्रीसाइंस बेचने की तैयारी में

ट्रैक्टर-ट्रक टायर के बाद अब दोपहिया और पैसेंजर कार टायर पर फोकस; नए प्लांट्स, लोकल प्रोडक्शन और ब्रांडिंग से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति

मुंबई: प्राइवेट इक्विटी फर्म केदारा कैपिटल अब यूनिवर्सल न्यूट्रीसाइंस (UNS) को 3,000 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स और फूड सप्लीमेंट्स सेगमेंट में सक्रिय है, जिसमें प्रोटीन पाउडर, विटामिन्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स शामिल हैं। केडारा ने 2021 में UNS में निवेश किया था और अब तीन-चार साल में अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए एग्जिट प्लान बना रही है।

कंपनी ने कई बड़े निवेशकों और कॉर्पोरेट खरीदारों से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इस सौदे में वैल्यूएशन 3,000 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। UNS का टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ा है और यह भारत के बढ़ते हेल्थ सप्लीमेंट बाजार में मजबूत स्थिति रखती है। बाजार में प्रोटीन और विटामिन सप्लीमेंट्स की मांग में 20-25% सालाना वृद्धि हो रही है।

केदारा कैपिटल के इस एग्जिट से भारतीय न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर में बड़ा सौदा होने की संभावना है। संभावित खरीदारों में घरेलू फार्मा दिग्गज और विदेशी निवेशक शामिल हैं। यह सौदा फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि UNS का अधिग्रहण करने वाली कंपनी को बाजार में मजबूत ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलेगा।

केदारा ने पिछले कुछ वर्षों में कई सफल एग्जिट किए हैं। यह सौदा फर्म के लिए भी बड़ा मुनाफा लेकर आएगा। भारतीय न्यूट्रास्यूटिकल बाजार 2030 तक 50,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। यह डील सेक्टर में नए निवेश और विस्तार की लहर ला सकती है।

FMCG Firms Weigh Smaller Packs, Price Hikes to Offset Crude Shock

Rising Crude Oil Prices Push Input Costs Up 12-18%; Firms Eye Smaller Packs and 4-8% Price Increases to Protect Margins Amid Weak Rural Demand

Chandigarh: India's fast-moving consumer goods (FMCG) companies are facing renewed margin pressure as global crude oil prices surge beyond $90 per barrel, driven by Middle East tensions and supply disruptions. With crude accounting for 8-15% of input costs in personal care, household, and packaged food products, major players are actively debating two key responses: shrinking pack sizes and moderate price hikes.

Industry sources say companies such as Hindustan Unilever, ITC, Godrej Consumer, Marico, and Dabur are reviewing portfolio-level actions. Palm oil, paraffin wax, surfactants, and packaging materials derivatives of crude have seen 12-18% cost inflation over the past three months. At the same time, rural demand remains sluggish due to uneven monsoon recovery and high food inflation, limiting the ability to pass on full cost increases without losing volume.

Shrinking pack sizes (down-weighting) is emerging as the preferred first step for many brands. Popular shampoo sachets, toothpaste tubes, biscuit packs, and detergent pouches are likely to see 5-10% reduction in net content while retail prices remain unchanged or rise modestly. A second round of 4-8% price increases across soaps, hair oils, edible oils, and select staples is also under consideration, with roll-outs expected in phases between February and April 2026.

Down-weighting allows us to absorb some inflation without visibly hurting the consumer, said a senior executive from a leading FMCG house. Price hikes will be calibrated to protect volumes in a price-sensitive market.

Analysts warn that sustained crude above $95 could force sharper increases, risking demand destruction in lower-income segments. Rural markets, which contribute 35-40% of FMCG sales, are particularly vulnerable. Yet, urban premiumisation trends and growing quick-commerce penetration may help offset some volume loss.

FMCG stocks traded mixed on BSE, with defensive names holding steady while export-oriented players faced pressure. With Brent crude showing no immediate signs of cooling, the industry's balancing act between margin protection and volume preservation will remain in sharp focus through the first half of 2026.

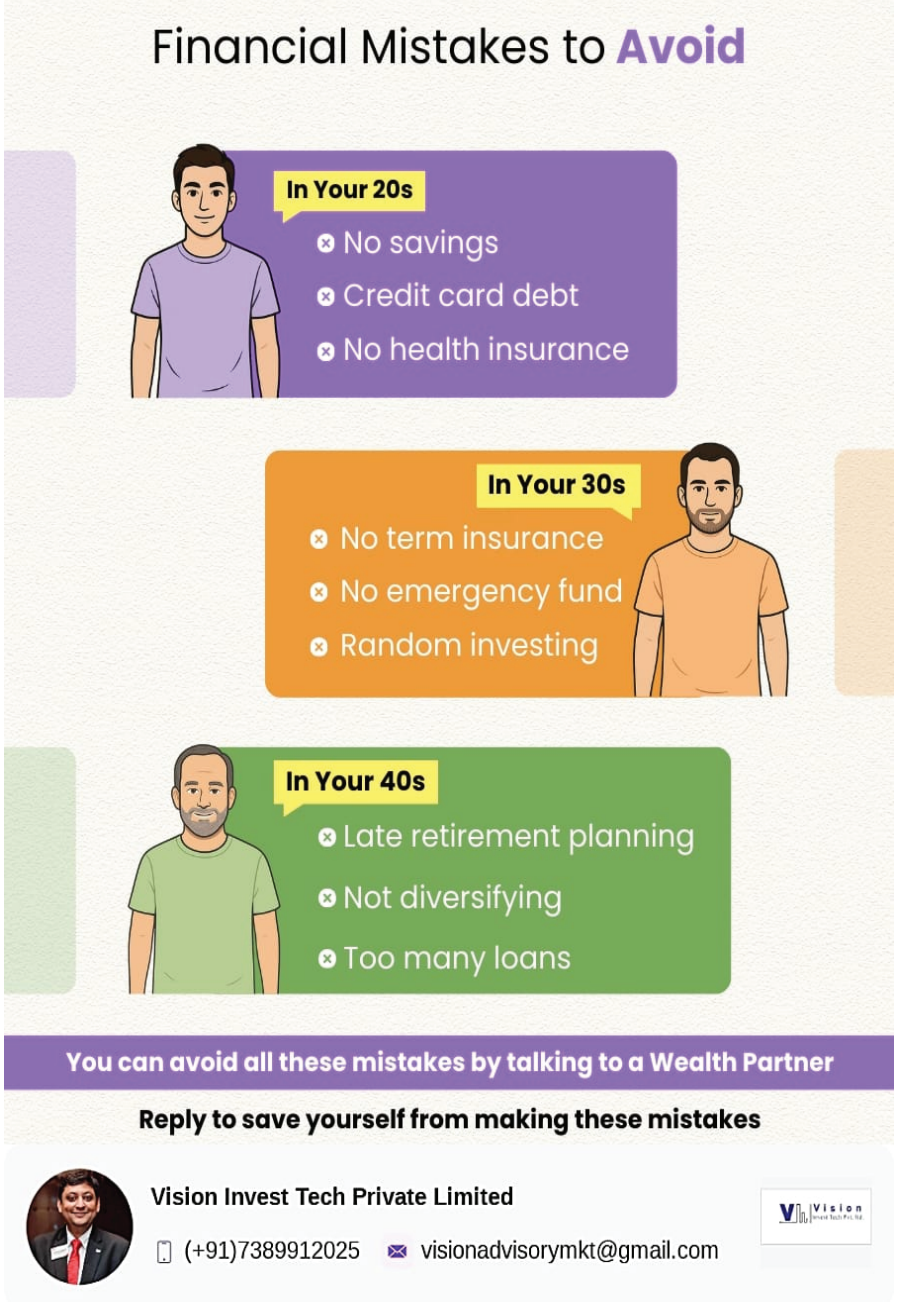

ABB Commits $75 Million to Expand India Manufacturing and R&D

Global Technology Leader Boosts Capacity in Electrification and Automation; New Facilities to Support India's Industrial Growth and Energy Transition

Mumbai: ABB, the Swiss-Swedish multinational technology company, has announced a $75 million (approximately ₹630 crore) investment to expand its manufacturing and research & development (R&D) footprint in India. The multi-year plan includes setting up new production lines, upgrading existing facilities, and strengthening R&D centres to cater to growing demand for electrification, automation, robotics, and industrial digital solutions.

The investment will primarily focus on ABB's Bengaluru and Nashik plants, where the company manufactures low- and medium-voltage switchgear, motors, drives, and control systems. A new dedicated R&D hub in Bengaluru will work on next-generation technologies such as smart grids, EV charging infrastructure, and AI-enabled predictive maintenance tools. ABB aims to increase localisation levels to over 90% for key products, aligning with the government's 'Make in India' initiative.

India is one of our most important growth markets, said ABB India Managing Director Sanjeev Sharma. This investment will enhance our ability to serve customers faster, introduce innovative solutions locally, and support India's journey toward sustainable industrialisation and net-zero goals.

The expansion is expected to create over 1,000 skilled jobs and strengthen ABB's supply chain resilience amid global disruptions. The company already derives nearly 10% of its global revenue from India, with strong demand from infrastructure, renewables, data centres, and manufacturing sectors.

Industry analysts welcomed the commitment, noting that India's electrification and automation market is growing at 12–15% annually. ABB's increased focus on R&D will also help develop India-specific solutions, such as cost-effective robotics for SMEs and advanced grid technologies for renewable integration.

ABB India shares rose on BSE following the announcement, reflecting investor confidence in the company's long-term strategy. As India targets 500 GW of non-fossil capacity by 2030 and deeper industrial digitisation, ABB's investment reinforces its role as a key enabler of the country's energy and manufacturing transformation.

Raw Nerve: Drugs May Get Costlier as Prices of Ingredients Surge 30%

Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) Hit by Crude Oil Spike and Supply Chain Disruptions; Pharma Companies Signal 8-12% Price Hikes in Coming Months

Pune: India's pharmaceutical industry, the world's largest supplier of generic medicines, is bracing for another round of price increases as the cost of key active pharmaceutical ingredients (APIs) has jumped 30% in the past six months. Rising crude oil prices, persistent supply chain bottlenecks, and currency depreciation have driven up production costs for paracetamol, antibiotics, anti-diabetics, cardiovascular drugs, and painkillers.

Industry sources say major API intermediates such as benzene derivatives, solvents, and petrochemical-based building blocks have seen sharp inflation. For many essential medicines, raw material costs now account for 40-55% of the total manufacturing expense, leaving little room for absorption. Leading drugmakers including Sun Pharma, Cipla, Dr Reddy's, Lupin, and Zydus are expected to pass on 8-12% of the cost increase to consumers through price revisions in the next two quarters.

The Organisation of Pharmaceutical Producers of India (OPPI) has warned that without government intervention such as expedited duty waivers on critical imports or enhanced PLI incentives affordability of essential drugs could be hit hard, especially for chronic therapies. The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) currently caps price increases at 10% annually for scheduled drugs, but companies may seek exemptions citing extraordinary input cost pressures.

The surge follows a similar cost wave in late 2024-early 2025, when API prices rose 18-22%. Rural and low-income households, which rely heavily on generics, are likely to feel the maximum impact. Meanwhile, export realisations remain under pressure due to global competition and price controls in regulated markets.

Experts urge faster localisation of high-cost APIs through the ongoing PLI scheme and stronger supply chain diversification to reduce dependence on China (still source of 65-70% of India's API imports). Until relief measures take effect, patients may face higher out-of-pocket expenses for both acute and chronic treatments.

PhonePe Launches 'RuPay On-The-Go' Card to Simplify Commuter Payments Across the Country

Contactless, Rechargeable Prepaid Card Enables Seamless Metro, Bus, and Toll Payments; Targets 50 million Users in First Year with Zero-Fee Loading

Ludhiana: PhonePe, India's leading digital payments platform, has launched 'RuPay On-The-Go', a contactless prepaid card designed specifically to simplify daily commuter payments across metros, buses, toll plazas, and parking facilities nationwide. The new card, issued in partnership with NPCI and RuPay, aims to make public transport and small-ticket offline payments faster, safer, and more convenient for millions of Indians.

The RuPay On-The-Go card works on the widely accepted RuPay network and supports instant top-ups directly from the PhonePe app using UPI, bank accounts, or credit/debit cards. It can be used for tap-and-pay transactions at metro gates, bus validators, FASTag toll lanes (where enabled), and retail outlets accepting RuPay contactless payments. The card requires no physical KYC for loading up to ₹10,000 and offers zero fees on loading and usage within the monthly limit.

PhonePe CEO Sameer Nigam said, Commuters across India still face cash hassles or slow QR-based payments in crowded metros and buses. RuPay On-The-Go combines the simplicity of a physical card with the speed of digital loading, making every day travel truly frictionless.

The card is initially available in Delhi-NCR, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata, and Ahmedabad, with nationwide rollout planned over the next six months. PhonePe aims to onboard 50 million users in the first year by offering cashback

exclusive commuter passes, and integration with state transport apps.

Industry analysts welcomed the move, noting that India's public transport payment market remains largely cash-dominated despite UPI's dominance in retail. The card addresses a key gap in offline small-ticket transit payments and is expected to accelerate the shift to digital in semi-urban and tier-2/3 cities.

PhonePe's parent company shares reacted positively. As India pushes for a less-cash society, RuPay On-The-Go could become a game-changer for daily commuters and further solidify PhonePe's position in the everyday payments' ecosystem

NHAI-Backed Raajmarg Infra InvIT Raises Rs 1,728 Crore from Anchor Investors

Strong Institutional Demand Signals Confidence in Toll Road Assets; Rs 4,000 Cr InvIT Issue Fully Subscribed Ahead of Public Offer

Mumbai: Raajmarg Yug Highway InvIT, backed by the National Highways Authority of India (NHAI), has successfully raised Rs 1,728 crore from anchor investors ahead of its Rs 4,000 crore initial public offering (IPO). The InvIT, sponsored by Cube Highways and Transportation Assets India, received overwhelming response from marquee domestic and global institutional investors, reflecting strong confidence in India's toll road sector and the InvIT structure.

The anchor book was subscribed at the upper end of the price band, with participation from leading mutual funds, insurance companies, pension funds, and foreign portfolio investors. Key allocations included major names from the insurance and pension space, underscoring the appeal of stable, long-term cash flow-generating assets backed by government entities.

Raajmarg InvIT comprises a portfolio of four high-traffic national highway stretches totaling 460 km in Rajasthan and Gujarat. These assets benefit from strong toll revenue growth, inflation-linked toll hikes, and low maintenance requirements, making them attractive for yield-seeking investors.

This robust anchor response validates the quality of our assets and the attractiveness of InvITs as an investment class, said a spokesperson for Cube Highways. The InvIT is expected to offer attractive distribution yields, supported by predictable cash flows from NHAI-announced toll plazas.

The public issue, comprising fresh units and an offer for sale, will open shortly. Analysts expect strong retail and HNI participation, given the government backing, stable revenue model, and growing interest in infrastructure yield products.

The successful anchor round comes amid renewed focus on InvITs as a vehicle for monetising operational road assets. With India's highway network expanding rapidly under Bharatmala and other initiatives, such InvITs provide investors stable returns while freeing up capital for new projects.

Raajmarg InvIT's fundraising success highlights the maturity of India's infrastructure financing ecosystem and the rising appetite for listed yield-generating assets.

IRDAI ने Allianz Jio Reinsurance और Kiwi General को मंजूरी दी

जियो और Allianz की रीइंश्योरेंस कंपनी, Kiwi का जनरल इंश्योरेंस कारोबार शुरू; बीमा क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों को बेहतर विकल्प और सस्ती पॉलिसी की उम्मीद

नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने दो बड़ी कंपनियों को मंजूरी दे दी है। Allianz Jio Reinsurance और Kiwi General Insurance को ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति मिल गई है। यह बीमा क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प लाने वाला कदम है।

Allianz Jio Reinsurance जर्मनी की Allianz और रिलायंस जियो की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह रीइंश्योरेंस (बीमा कंपनियों का बीमा) का कारोबार करेगी। कंपनी भारतीय बीमा कंपनियों को रिस्क शेयर करने और बड़े क्लेम्स से बचाव में मदद करेगी। इससे बीमा कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी और पॉलिसीधारकों को सस्ती और मजबूत कवर मिल सकता है। Allianz की वैश्विक विशेषज्ञता और जियो की डिजिटल ताकत से यह कंपनी तेजी से बाजार में जगह बनाएगी।

दूसरी ओर, Kiwi General Insurance न्यूजीलैंड की Kiwi Insurance की भारतीय इकाई है। इसे जनरल इंश्योरेंस (मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी आदि) का लाइसेंस मिला है। Kiwi डिजिटल-फर्स्ट मॉडल पर काम करती है, जो तेज क्लेम सेटलमेंट और आसान पॉलिसी खरीद पर फोकस करती है। कंपनी ने कहा कि वह सस्ती प्रीमियम और बेहतर सर्विस के साथ बाजार में आएगी।

बीमा विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों कंपनियों की एंट्री से बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रीइंश्योरेंस से कंपनियों की रिस्क क्षमता बढ़ेगी और जनरल इंश्योरेंस में ग्राहकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। भारत में बीमा घनत्व अभी भी कम है और 2047 तक 'बीमा सबके लिए' लक्ष्य को हासिल करने में यह कदम महत्वपूर्ण है।

दोनों कंपनियों के शेयरधारक और बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। यह भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश और डिजिटल इनोवेशन का नया दौर शुरू करेगा।

पेंट कंपनियां चिंतित: कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से मुनाफा कम हो सकता है

कच्चे तेल में 20% उछाल से इनपुट लागत बढ़ी, मार्जिन 2-4% तक सिकुड़ने का खतरा; कंपनियां कीमत बढ़ाने या पैक साइज घटाने पर विचार कर रही हैं

नई दिल्ली: कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से पेंट उद्योग में मुनाफे पर गहरा संकट मंडरा रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सॉल्वेंट्स, रेजिन और पैकेजिंग मटेरियल की लागत 15-20% तक बढ़ गई है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, केनडल और डुलक्स जैसी प्रमुख कंपनियों के मार्जिन पर 2-4% का दबाव पड़ने का अनुमान है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि पेंट सेक्टर में कच्चे तेल का योगदान कुल लागत का 30-35% है। पिछले तीन महीनों में इनपुट कॉस्ट में यह बढ़ोतरी मार्जिन को सीधे प्रभावित कर रही है। कंपनियां अब दो विकल्पों पर विचार कर रही हैं, एक, उत्पादों की कीमत 5-8% तक बढ़ाना और दूसरा, पैक साइज घटाकर (डाउन-वेटिंग) ग्राहकों को वही कीमत में कम माल्रा देना।एशियन पेंट्स के एक प्रवक्ता ने कहा, हम लागत बढ़ोतरी को पूरी तरह ग्राहकों पर नहीं डालना चाहते, लेकिन मार्जिन बचाने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं। बर्जर पेंट्स ने भी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स में 3-5% की बढ़ोतरी की है। हालांकि, ग्रामीण बाजार में मांग अभी भी कमजोर है, जिससे कीमत बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार जाती हैं, तो पेंट कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इससे मध्यम वर्ग के घरेलू पेंटिंग पर असर पड़ेगा। उद्योग का FY26 में 8-10% ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें इस लक्ष्य को प्रभावित कर सकती हैं।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.
EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23151	25121	24712	23932	23523	22743	22334	21554
BANK NIFTY	53758	59423	58260	56009	54846	52595	51432	49181
SENSEX	76034	80405	79465	77750	76810	75095	74155	72440
FINNIFTY	25139	27655	27135	26137	25617	24619	24099	23101
MIDCAP	12618	13799	13547	13083	12831	12367	12115	11651
ACC	1377	1582	1540	1458	1416	1334	1292	1210
AXISBANK	1199	1407	1364	1281	1238	1155	1112	1029
ABCAPITAL	310	359	349	329	319	299	289	269
BHARTIARTL	1806	1964	1923	1864	1823	1764	1723	1664
BHEL	260	293	281	271	259	249	237	227
BIOCON	383	422	412	398	388	374	364	350
BEL	439	497	484	461	448	425	412	389
CDSL	1178	1326	1294	1236	1204	1146	1114	1056
DATAPATTERN	3205	3907	3754	3479	3326	3051	2898	2623
ESCORTS	3118	3659	3537	3327	3205	2995	2873	2663
EICHERMOTOR	6765	8240	7907	7336	7003	6432	6099	5528
FEDERAL BANK	263	294	288	275	269	256	250	237
GRINFRAPOJECT	925	1079	1040	982	943	885	846	788
HDFCBANK	817	890	874	845	829	800	784	755
HCLTECH	1329	1418	1397	1363	1342	1308	1287	1253
HINDUNILVR	2162	2336	2280	2221	2165	2106	2050	1991
HAL	3912	4257	4181	4046	3970	3835	3759	3624
HYUNDAI	2018	2262	2193	2106	2037	1950	1881	1794
IOC	157	178	172	165	159	152	146	139
ICICIBANK	1254	1362	1339	1296	1273	1230	1207	1164
INFY	1251	1378	1350	1300	1272	1222	1194	1144
ITC	302	318	315	308	305	298	295	288
KOTAKBNK	367	417	406	386	375	355	344	324
LICHOUSING	497	548	535	516	503	484	471	452
LT	3444	4349	4161	3802	3614	3255	3067	2708
LUPIN	2306	2455	2417	2361	2323	2267	2229	2173
MARUTI	12615	15009	14478	13547	13016	12085	11554	10623
M&M	2940	3578	3443	3192	3057	2806	2671	2420
MGL	1034	1153	1119	1077	1043	1001	967	925
MAZGAONDOC	2324	2686	2613	2468	2395	2250	2177	2032
PFC	405	460	440	423	403	386	366	349
RECLTD	331	374	362	346	334	318	306	290
RELIANCE	1382	1485	1459	1421	1395	1357	1331	1293
SBIN	1046	1173	1147	1096	1070	1019	993	942
SUNPHARMA	1802	1913	1878	1840	1805	1767	1732	1694
SHRIRAMFINANCE	1006	1222	1150	1078	1006	934	862	790
TITAN	4073	4407	4324	4199	4116	3991	3908	3783
TCS	2413	2679	2620	2516	2457	2353	2294	2190
TATAMOTORS	314	377	362	338	323	299	284	260
UPL	609	662	649	629	616	596	583	563
VALIENT	208	241	233	220	212	199	191	178
WIPRO	198	218	212	205	199	192	186	179

भारत की सोलर इंडस्ट्री ने मांगा 25,000 करोड़ रुपये का समर्थन: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने की मांग

अतिरिक्त क्षमता और गिरती कीमतों से कंपनियां संकट में, PLI स्कीम का विस्तार और सब्सिडी जरूरी; 2030 तक 500 GW लक्ष्य पर खतरा

नई दिल्ली: भारत की सोलर इंडस्ट्री ने सरकार से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त समर्थन की मांग की है। NSEFI और SEIA जैसे संगठनों ने कहा कि PLI स्कीम के तहत स्थापित 100 GW से अधिक सोलर सेल और मॉड्यूल की क्षमता अब ग्लट (अधिकता) में बदल चुकी है। घरेलू मांग 30-35 GW के आसपास रहने से उत्पादन क्षमता का 60-70% बेकार पड़ा है।

सोलर मॉड्यूल की कीमतें 10 रुपये/वाट से भी नीचे गिर चुकी हैं, जिससे कई कंपनियां घाटे में चल रही हैं। चीन से सस्ते आयात और वैश्विक बाजार में मंदी ने स्थिति और बिगाड़ दी है। इंडस्ट्री का कहना है कि बिना अतिरिक्त समर्थन के कई प्लांट बंद हो सकते हैं, जिससे हजारों नौकरियां जा सकती हैं और 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल ऊर्जा का लक्ष्य प्रभावित होगा।

उद्योग ने सरकार से PLI स्कीम का विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, 5-7 साल के लिए सब्सिडी और सोलर पार्क्स में अतिरिक्त छूट की मांग की है। साथ ही, घरेलू मांग बढ़ाने के लिए रूफटॉप सोलर और ग्रिड-स्केल प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने का सुझाव दिया है। NSEFI के प्रेसिडेंट ने कहा, "हमारी क्षमता विश्व स्तर की है, लेकिन मांग और कीमतों का संतुलन नहीं है। सरकार का समर्थन जरूरी है, वरना यह बूम ग्लट में बदल जाएगा।"

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग सपना खतरे में पड़ सकता है। यह क्षेत्र 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्तंभ है। सरकार जल्द ही इस पर विचार कर रही है।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in